

FEBRUARY  
2025



# MASIK PATRIKA

**WESTERN U.P. CHAMBER  
OF COMMERCE AND  
INDUSTRY**

**"CHAMBER BHAWAN" BOMBAY  
BAZAR, MEERUT CANTT-250001  
(U.P.) INDIA**

Phone No : (0121)-4346686,2661177

Fax : 0121-2661685

Website : [www.wupcc.org](http://www.wupcc.org)

E-mail : [wupcc@rediffmail.com](mailto:wupcc@rediffmail.com)



- Patron

Dr. Mahendra Kumar Modi

- President

Dr. Ram Kumar Gupta

- Sr. Vice President

Shri G.C. Sharma

- Jr. Vice President

Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- Secretary / Editor

Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- Chairman

Shri Rahul Das

- Co-Chairman

Shri Sushil Jain

- Members

Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

Shri Rakesh Kohli

Shri Trilok Anand

Shri Rajendra Singh

Shri Atul Bhushan Gupta

- Co-Editor

Ms. Rekha Yadav



# INDEX

- बैंकों के जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगेगा
- अपनी सीबीडीसी योजना पर आगे बढ़ता रहेगा आरबीआइ
- नक्शा मंजूरी के लिए देना होगा 30 हजार तक शुल्क
- ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज विवरण दर्ज करें
- लाकर में सामान रखकर कहीं भी करें यात्रा, रैपिड स्टेशन पर मंगवाएं पार्सल
- सभी पीएफ खातों को मिलाना आसान हुआ
- सरकारी कार्यालयों में अब एक मार्च से लागू होगी ई-आफिस व्यवस्था
- जिन संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण जरूरी नहीं, उन्हें भी मिलेगा अस्थायी टीन
- मार्च तक खत्म करें जीएसटी के सभी पुराने मामले
- FM focuses on critical growth levers in 2025 budget to drive inclusive development
- बजट में एमएसएमई में दिया गया ध्यान
- RBI tightens norms for imposing penalty under payment systems law
- Bank credit to MSMEs growing faster than credit to large enterprises: Economic Survey - 2025

- DGFT upgrades platform for issuing electronic certificate of origin
- UP govt approves new aerospace and defence policy, reforms in FDI
- RBI forms new advisory committee to evaluate licenses for Universal and Small Finance Banks
- India to work with EU on developing modern tech, says Piyush Goyal
- RBI Introduces Measures To Boost Cross-Border Transactions In Indian Rupee
- DPIIT, ITC join hands to help startups in manufacturing sector
- Labour ministry to set up career counseling centers in major universities
- Govt approves 2 new payment methods for rooftop solar under PM Surya Ghar

## बैंकों के जुमाने पर जीएसटी नहीं लगेगा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वसूले जाने वाले जुमाना शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं होगा। बोर्ड ने एक परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतान संग्रहकर्ताओं (पेमेंट एग्रीगेटर्स) द्वारा 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा।

जीएसटी की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा लगाया गया जुमाना शुल्क, ऋण अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए होता है, इसलिए यह जीएसटी के दायरे में नहीं आता। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड ने जुमाना शुल्क पर जीएसटी को लेकर अनिश्चितता दूर कर दी है। इससे ऋण लेने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही व्याख्या संबंधी विवादों का निपटारा होगा।

वहीं, भुगतान संग्रहकर्ताओं (पीए) से जुड़े कर मामले में बोर्ड ने कहा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या अन्य भुगतान कार्ड के माध्यम से 2,000 रुपये तक के एकल लेनदेन पर जीएसटी छूट लागू होगी। बोर्ड ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि भुगतान संग्रहकर्ता और भुगतान गेटवे में अंतर है। भुगतान गेटवे केवल तकनीकी सुविधा पतार करते हैं और धन प्रबंधन में शामिल नहीं होते।



## अपनी सीबीडीसी योजना पर आगे बढ़ता रहेगा आरबी.

### आइ

ट्रंप प्रशासन की तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को प्रतिबंधित करने से दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों के निर्देशन में डिजिटल करेंसी की व्यवस्था को लागू करने की भारत की मुहिम को धक्का लगा है। हालांकि घरेलू स्तर पर आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी व्यवस्था को प्रसारित करने की योजना को लेकर ना तो सरकार की सोच बदली है और ना ही आरबीआई पीछे हटा है। आरबीआई ने दिसंबर, 2022 को देश के कुछ चयनित बैंकों के चयनित शाखाओं के जरिये सीबीडीसी को लागू किया था और तब यह बताया गया था कि यह निजी क्षेत्र की डिजिटल करेंसी (क्रिप्टोकॉर्सेस व अन्य) की चुनौतियों को थामने का काम करेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीबीडीसी को प्रतिबंधित किया है बल्कि

क्रिप्टोकॉर्सेस को हरी झंडी दिखाते हुए अमेरिका को इसका सबसे बड़ा केंद्र बनाने का भी एलान किया है। अमेरिका की नई सरकार के उक्त फैसलों के भारत पर प्रभाव को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इसका एक स्पष्ट असर सीबीडीसी को लेकर जी-20 की तैयारियों पर होने का खतरा है। नवंबर, 2020 के शंखर सम्मेलन में जी-20 देशों ने विभिन्न देशों के बीच डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को लेकर घोषणा की थी। तब बताया गया था कि मौजूदा भुगतान व्यवस्था के मुकाबले सीबीडीसी काफी सस्ता, पारदर्शी व सुविधाजनक होगा। बाद में भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 की बैठक में इसे एक अहम मुद्दा बनाया गया था। अहमदाबाद में जी-20 के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और आइएमएफ, विश्व बैंक जैसे दूसरे

वैश्विक संस्थानों की बैठक में इस बारे में बहस हुई कि कैसे सीबीडीसी का इस्तेमाल व्यापक आर्थिक फायदे के लिए किया जाए। नई दिल्ली घोषणा-पत्र में भी इसका जिक्र किया गया। इस बीच भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, यूएई समेत 36 देशों में सीबीडीसी पर प्रायोगिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। जी-20 ने वर्ष 2027 तक सीबीडीसी की एक मजबूत व्यवस्था दुनियाभर में बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ से इससे हाथ खींचने से इस यो पर उल्टा असर पड़ना संभव है।

### भारत में 50 लाख लोग कर रहे सीबीडीसी का इस्तेमाल

आरबीआइ की तरफ से भी सीबीडीसी को ज्यादा व्यापक बनाने का काम धीरे-धीरे चल रहा है। आरबीआइ की तरफ से यह भी बताया गया था कि जून, 2024 तक भारत में 50 लाख ग्राहक सीबीडीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संख्या एक वर्ष पहले सिर्फ 13 लाख थी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपनी फ्लैगशिप सुभद्रा योजना को भी आरबीआइ की पायलट सीबीडीसी से जोड़ने का काम किया है।

### अभी 15 भारतीय बैंक जारी कर रहे सीबीडीसी

दिल्ली स्थित मुख्यालय वाले एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरबीआइ की तरफ से सीबीडीसी की रफ्तार धीमी करने का कोई संकेत नहीं है। हालांकि, अभी इसे पूरी तरह से लांच करने को लेकर भी विमर्श नहीं चल रहा। सीबीडीसी आरबीआइ की खाता (डिजिटल वालेट) खोलना पड़ता है और इसका खास एप ईआर डाउनलोड करना होता है। मान्यता वाली डिजिटल करेंसी है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को एक विशेष डिजिटल यह भारतीय रुपये में भुगतान करने या स्वीकार करने का डिजिटलमाध्यम है। अभी 15 भारतीय बैंक सीबीडीसी जारी कर रहे हैं।

1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध लगाने का नहीं पड़ेगा कोई विशेष असर
2. दिसंबर, 2022 में आरबीआइ ने डिजिटल करेंसी को प्रायोगिक तौर पर किया था लागू

## नक्शा मंजूरी के लिए देना होगा 30 हजार तक शुल्क

शहरों में नक्शा पास कराने पर 10 हजार से 30 हजार रुपये तक परमिट शुल्क देना होगा। साथ ही आवासीय, व्यावसायिक या मॉल निर्माण से पड़ने वाले इंपैक्ट के एवज में भी शुल्क की वसूली होगी। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण) नियमावली जारी हो गई है। एक हेक्टेयर तक भूमि पर निर्माण पर 10 हजार रुपये, एक से ढाई हेक्टेयर तक पर 20 हजार, ढाई से पांच हेक्टेयर तक 30 हजार, पांच हेक्टेयर से अधिक पर 30 हजार के साथ हर पांच हेक्टेयर पर अतिरिक्त 15 हजार रुपये विकास शुल्क लगेगा। वाणिज्यिक, शापिंग कांप्लेक्स, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग, कार्यालय निर्माण पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, समूह आवास पर 15 रुपये, आवासीय या अन्य उपयोग पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भवन परमिट शुल्क देना होगा। दोवारा निर्माण, अतिरिक्त निर्माण या बदलाव पर नए भवन निर्माण के बराबर शुल्क देना होगा। निरीक्षण शुल्क 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लिया जाएगा। एक मंजिला, बहुमंजिला या फर्शीय क्षेत्रफल के हिसाब से 20 रुपये

प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (इंपैक्ट शुल्क का निर्धारण और वसूली) नियमावली भी जारी कर दी गई है। इसका फार्मूला कुछ छ ऐसे तय किया गया है। सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने पर 0.25, आवासीय और गांव की आबादी में निर्माण पर 0.25 यातायात व परिवहन पर 0.30, औद्योगिक 40, आवासीय 50, कार्यालय: 100 व वाणिज्यिक पर 150 के हिसाब से गुणा करते हुए गणना की जाएगी।

उदाहरण के लिए भूखंड का क्षेत्रफल गुणे के सर्किल रेट, इंपैक्ट शुल्क गुणे 0.25 हिसाब से गणना किया जाएगा। इस हिसाब से जो दर निकलेगी उसे शुल्क के रूप में वसूला जाएगा।

1. शहरों में भवन का नक्शा पास करना होगा महंगा
2. परमिट, इंपैक्ट शुल्क की भी वसूली होगी

## ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज विवरण दर्ज करें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल से जुड़े विवरणों में बदलाव करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

अब सदस्य अपना नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण बिना किसी दस्तावेज के अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार से सत्यापित है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और लंबित अनुरोधों को तेजी से निपटाना है।

पहले, बदलाव के लिए नियोक्ता से सत्यापन की आवश्यकता होती थी, जिसमें करीब 28 दिन का समय लगता था। अब करीब 45 फीसदी

अनुरोधों को सदस्यों द्वारा स्व-अनुमोदित किया जा सकता है। अन्य 50 फीसदी को ईपीएफओ की भागीदारी के बिना केवल नियोक्ता की मंजूरी से निपटाया जा सकता है।

### चार लाख अनुरोध लंबित

प्रोफाइल अपडेट के करीब 3.9 लाख अनुरोध लंबित हैं। ऐसे सदस्य अब लंबित अनुरोध वापस ले सकते हैं। और फिर से आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27 फीसदी प्रोफाइल और केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं। माना जा रहा है कि नई प्रक्रिया से इन शिकायतों में भारी कमी आएगी।

### क्या है नई प्रक्रिया

दस्तावेज जमा करने और नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आधार के साथ यूएएन का लिंक होना ही पर्याप्त है। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह उन्नत किया है कि यह स्वतः आधार से संबंधित विवरण की पुष्टि कर लेगा। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर अनुरोध करना होगा।

### विवरण ऐसे अपडेट करें

1. पोर्टल (<https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/>) पर लॉगिन करें।
2. मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स विकल्प में जाकर जानकारी भरें।
3. यदि आवश्यक हो तो सहायक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

### इनमें बदलाव कर सकेंगे

नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, शामिल होने और जाने की तिथियां

# लॉकर में सामान रखकर कहीं भी करें यात्रा, रैपिड स्टेशन पर मंगवाएं पार्सल

साहिबाबाद व गाजियाबाद स्टेशन पर स्मार्ट लॉकर की सुविधा शुरू

कभी-कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि बिना सामान लिए ही किसी स्थान पर जाना है, लेकिन मजबूरी यह है कि साथ में जो सामान है उसे कहां रखें, किसे बुलाकर सौंपें। इसी के साथ कभी कभार आप ई-कामर्स वेबसाइट से ऐसा सामान मंगवाना चाहते हैं कि स्टेशन से उतरने के बाद या यात्रा शुरू करने से पहले ही डिलीवरी मैन से ले लेंगे।

उसी अनुरूप समय और स्थान का चयन करते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश समय से नहीं पहुंचे तो डिलीवरी मैन किसे सामान दे इसलिए अधिकांश लोग सुरक्षित पते पर ही आर्डर करते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने कर दिया है। सभी स्टेशनों पर सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिलेगी। इस लॉकर में चाहे आप स्वयं सामान रखें, कोई स्वजन रखे या फिर डिलीवरी मैन। इस लॉकर का लाभ उठाने के लिए प्रति घंटे की दर से किराया चुकाना होगा। साहिकबाद और गाजियाबाद स्टेशन पर स्मार्ट लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसकी सुविधा बाकी सभी स्टेशनों पर भी मिलने लगेगी।

इस तरह से यात्री उठा सकेंगे लॉकर का लाभ यात्री को लॉकर पर दी गई डिजिटल स्क्रीन पर अपना विवरण डालकर एकाउंट बनाना होगा। इसके बाद यात्री अपनी आवश्यकता के अनुसार लॉकर का किराया दे सकते हैं। यात्री जरूरतों के आधार पर स्मार्ट लॉकर में स्माल, मीडियम और लार्ज-एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। एक से

छह घंटे तक की अवधि तक के लिए लॉकर बुक करने का विकल्प दिया गया है। बुक करने को समय और लॉकर का आकार चयनित करना होगा। इस सुविधा के लिए भुगतान यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। अगर किसी यात्री का सामान निर्धारित बुकिंग टाइम से ज्यादा समय तक लॉकर में रहता है, तो लॉकर से सामान निकालने के लिए लॉकर के साइज के हिसाब से प्रतिघंटे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान करने बाद लॉकर चुक हो जाएगा। लॉकर के बुक होने पर उपभोक्ता को एक एक्सेस कोड मिलेगा, जिसे लॉकर को खोलने और बंद करने के लिए उपयोग किया जाएगा। लॉकर में सिक््योरिटी के लिए एक्सेस कोड दिया जाएगा, ताकि कोई और लॉकर न खोल सके। इस एक्सेस कोड का उपयोग एकर खोलने व बंद करने को सिर्फ एक बार ही किया जा सकेगा।

यह है किराया

1. स्माल लॉकर 20 रुपये प्रति घंटा।
2. मीडियम लॉकर 30 रुपये प्रति घंटा।
3. लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर 40 रुपये प्रतिघंटा।

नमो भारत कनेक्ट एप पर भी बुक कर सकेंगे लॉकर

जल्द ही इस लॉकर को बुक करने की सुविधा नमो भारत कनेक्ट एप पर भी उपलब्ध होगी। एप में रेंट ए लॉकर का विकल्प दिया जाएगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद स्टेशन का नाम और तारीख का चयन करना होगा।

डिलीवरी मैन ऐसे रखेगा ई-कामर्स का पार्सल

अगर यात्री को ई-कामर्स पार्सल मंगाना है तो उसे मोबाइल एप या फिर स्टेशन के लॉकर पर खाता खोलने के बाद सामान बुक करने का समय, स्थान व साइज बुक करनी होगी। जो एक्सेस कोड यात्री को मिलेगा वह कोड और फोन नंबर डिलीवरी मैन को बताना होगा। जब डिलीवरी मैन स्टेशन में पहुंचेगा तो वहां सुरक्षा जांच के बाद नमो भारत स्टेशन के कस्टमर



केयर बूथ पर पार्सल डिलीवरी की जानकारी देनी होगी। पार्सल को लॉकर में रखने के बाद वह स्टेशन से बाहर आ जाएगा। यात्री पहुंचेगा तो कोड के आधार पर सामान निकाल सकेगा।

## सभी पीएफ खातों को मिलाया आसान हुआ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को अब नौकरी बदलने पर अपने जमा कोष को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यह प्रक्रिया अब काफी सरल बना दी गई है।

संगठन ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब अंशधारकों को पुराने या नए नियोक्ता या कंपनी के जरिए अपने कोष में रखी रकम को ट्रांसफर करने का नियम खत्म कर दिया गया है।

ईपीएफओ की तरफ से 15 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अब अंशधारक खुद ही अपने खाते को ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं।

कुछ खास मामलों में यदि आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो आपको अपनी पुरानी या नई कंपनी से पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। नए-पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को जोड़ने का काम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा।

### इन मामलों में मिलेगी राहत

1. एक ही यूएएन में ट्रांसफर (01/10/2017 को या उसके बाद जारी किया गया यूएएन) यदि एक ही यूएएन कई सदस्य आईडी और आधार से जुड़ा हुआ है।

2. विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (दोनों 01/10/2017 को या उसके बाद जारी किए) यदि किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई यूएएन हैं, तो सिस्टम उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानता है, जिससे एम्प्लॉयर की भागीदारी के बिना निर्बाध ट्रांसफर की

अनुमति मिलती है।

3. एक ही यूएएन के भीतर ट्रांसफर (01/10/2017 से पहले जारी किया गया यूएएन) पुराने यूएएन के लिए, पीएफ ट्रांसफर तभी काम करता है जब यूएएन आधार से जुड़ा हो और मेंबर आईडी में नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी मेल खाती हो।

4. विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (कम से कम एक 01/10/2017 से पहले जारी किया गया) कई यूएएन (एक पुराना) के बीच ट्रांसफर की अनुमति है यदि दोनों यूएएन एक ही आधार से जुड़े हों और व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि मेल खाते हों।

## सरकारी कार्यालयों में अब एक मार्च से लागू होगी ई-आफिस व्यवस्था

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अब एक मार्च से ई-आफिस व्यवस्था लागू होगी। इसे एक जनवरी से ही लागू कराया जाना था लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारण राज्य सरकार ने समय-सीमा बढ़ा दी है। सचिवालय से लेकर जिला, तहसील व ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी कार्यालयों में आफलाइन पत्रावली स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित तारीख से ई-आफिस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाए। ई आफिस व्यवस्था लागू करने में जो भी कार्य अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय से अक्षय अन्य जिल्ला, तहसील व ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के माध्यम से इंटरनेट सेवा जल्द उपलब्ध कराई जाए। एक मार्च के बाद सभी पत्रावलियां ई आफिस के माध्यम से आनलाइन ही उपलब्ध कराई जाएं।

# जिन संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण जरूरी नहीं, उन्हें भी मिलेगा अस्थायी टीन

जिन कारोबारी संस्थाओं को जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रावधानों के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है, वे अब अस्थायी पहचान संख्या (टीन) प्राप्त कर सकती हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इसके लिए जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। जीएसटी नियमों के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 40 लाख व 20 लाख रुपये के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों 1 के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में नियम 16ए पेश करते हुए कहा, जहां कोई

व्यक्ति प्रावधान के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कर भुगतान जरूरी है, वहां उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या दे सकता है। जीएसटी परिषद ने पिछले माह ऐसी संस्थाओं को टीआइ.एन जारी करने का निर्णय लिया था। इससे सुचारु कर भुगतान सुनिश्चित होगा। उन लोगों पर अनुपालन का बोझ घटेगा, जो कर योग्य गतिविधियों में नियमित शामिल नहीं होते हैं।

## मार्च तक खत्म करें जीएसटी के सभी पुराने मामले

सरकार का फैसला, सिर्फ टैक्स जमा कर जुर्माने और ब्याज दोनों से छूट पा सकते हैं कारोबारी

आयकर की तरह सरकार जीएसटी संबंधित विवादों को भी खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि कारोबारियों को राहत मिल सके। इसके तहत हाल ही में सरकार ने जीएसटी संबंधित सभी पुरानी डिमांड को खत्म करने का फैसला किया है। कारोबारियों को सिर्फ बकाये टैक्स का भुगतान करना होगा। सभी पुराने बकाये टैक्स भरने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। बकाए जीएसटी का भुगतान कर देने पर उन्हें टैक्स से जुड़े ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी।

सरकार की इस स्कीम के तहत जीएसटी संबंधित कोई भी डिमांड अगर किसी कारोबारी को अपने पोर्टल पर दिख रही है तो बह सिर्फ टैक्स की राशि को जमा कर जुर्माने और ब्याज दोनों से छूट पा सकता है। मान लीजिए

गत दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी थी। इस माह इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आयकर संबंधित पुराने विवादों को समाप्त करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास स्कीम ला चुकी है। उधर, इस साल से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी काम करने लगेगा। राज्यों की तरफ से ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति में देरी से ट्रिब्यूनल के संचालन में विलंब हो रहा है। देश भर 44 ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाना है। एक ट्रिब्यूनल में चार सदस्य होंगे।

सरकार ने आइटीसी पर भी दी बड़ी राहत

जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल सरकार ने जीएसटी संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) को लेकर भी कारोबारियों को बड़ी राहत दी थी। जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर कारोबारियों के आइटीसी फंस जाते हैं। पिछले साल सरकार ने कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के आइटीसी क्लेम के लिए एक साथ पुराने जीएसटी रिटर्न भरने का मौका दिया था।

लगातार लचीला होता जा रहा  
सरकार का रुख

जीएसटी विवादों से जुड़े वकील पीसी अग्रवाल ने बताया कि सरकार का रुख अब लगातार लचीला होता जा रहा है। अगर किसी कारोबारी पर जीएसटी का बकाया है तो सरकार से गुजारिश करने पर उन्हें टैक्स जमा करने की मोहलत आसानी से मिल जाती है। गलत रिटर्न को भी सुधार कर फिर से भरने की सुविधा दी गई है। वर्ष 2017 के जुलाई में जब जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी तो इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। हालांकि, सरकार के बकाये पर कोई कारोबारी जवाब भी नहीं देता है। कोई सवाद नहीं करता है तो टैक्स की राशि के मुताबिक कारोबारी को सजा का भी प्रविधान है।

## FM focuses on critical growth levers in 2025 budget to drive inclusive development

The Finance Minister, while presenting her eighth consecutive Budget on February , 2025, unveiled a range of growth-enhancing measures that will go a long way in realizing India's vision of a 'Viksit Bharat' by supporting inclusive growth and development, while promoting livelihoods and employment.

Bold initiatives including the huge income tax relief to the middle class with no income tax up to ₹12 lakh and indirect tax changes in the form of reduced customs duties on several consumer products are extremely welcome measures that will strongly boost consumption in the economy, by enhancing personal disposable incomes. It is commendable that despite the economic expansion measures, the Budget adheres to a path of fiscal consolidation, with the fiscal deficit target reduced to 4.4 per cent of GDP in 2025-26 from 4.8 per cent of GDP in 2024-25. At the same time, the Government continued its focus on infrastructure-led development with the capital expenditure target set at ₹ 11.2 trillion for 2025-26, an increase of 10.08 per cent from the previous year.

A host of forward-looking measures in the Union Budget with a strong emphasis on manufacturing, exports and investments will enhance India's integration into global value chains. On the other hand, proposals to boost social sectors such as health and education will nurture young talent, promote innovation and accelerate long-term economic growth.

It's aims to create a dynamic and vibrant MSME sector with measures such as promoting ease and cost of doing business, creating a future-ready workforce and a focus on digital public infrastructure. These in turn will revitalize India's manufacturing sector and provide a strong impetus to Make in India.

The measures focused on innovation including the ₹20,000 crore for implementing private sector-driven research, setting up of 50,000 Atal Tinkering Labs in Government schools and a Deep Tech Fund of Funds for catalysing next-gen startups will enhance research and development and create a resilient and self-reliant India. CII is happy to note the Budget's focus on labour-intensive sectors such as leather, toys, footwear and textiles as well as tourism, which will help generate large-scale employment and entrepreneurship opportunities while bolstering inclusive growth.

This year's Budget prioritizes critical growth engines and introduces several development measures for agriculture, urban development, the power sector, mining, and the financial sector as well as regulatory reforms, among others, that will promote global competitiveness and unlock India's massive growth potential. Overall, the 2025 Union Budget is a holistic, progressive and growth-oriented budget that rightfully focuses on its people and the economy, with an all-encompassing inclusive growth agenda.

## **Union Budget 2025-26**

### **Key Highlights & Summary**

#### **1. Fiscal & Economic Outlook**

- Fiscal Deficit: 4.4% of GDP (down from 4.8%).
- Revenue Receipts: ₹27.3 lakh crore | Capital Expenditure: ₹15.5 lakh crore.
- GDP Growth Projection: 10.1% nominal growth.
- Borrowing Plan: ₹14.82 trillion.

#### **2. Tax Reforms**

- No Tax for Income Up to ₹12 Lakh (New Regime).
- New Slabs: 5%-30% tax range based on income brackets.
- TDS on Rent Limit Raised: ₹2.4L → ₹6L.
- Senior Citizen Deduction: ₹50K → ₹1L.

#### **3. Major Investments & Reforms**

- ₹1.5 lakh crore interest-free loans to states for infra projects.
- ₹10 lakh crore Asset Monetization for new developments.
- Maritime Development Fund: ₹25,000 crore.
- AI Centers of Excellence: ₹500 crore investment.

#### 4. Agriculture & Rural Development

- ₹5 lakh crore Kisan Credit for 7.7 crore farmers.
- Makhana Board in Bihar & Mission for Cotton Productivity.
- Jal Jeevan Mission extended till 2028 for 100% water coverage.

#### 5. MSMEs & Startups Boost

- MSME Classification Revised: Turnover limits doubled.
- Custom Credit Cards for MSMEs (₹5 lakh limit for 10 lakh businesses).
- ₹10 lakh credit guarantee for startups & MSMEs.

#### 6. Social Welfare & Education

- PM Research Fellowship: 10,000 fellowships for IITs/IISc.
- Medical Expansion: 10,000 new seats added (target 75,000 in 5 years).
- Day Care Cancer Centers in all district hospitals.
- Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 for child nutrition.

#### 7. Financial & Banking Reforms

- FDI in Insurance raised to 100%.
- Partial Credit Enhancement Facility for infrastructure bonds.
- E-Shram Portal for gig & platform workers.

#### 8. Customs & Indirect Tax Reforms

- Customs Tariff Simplified: 7 slabs reduced.
- Duty Exemptions: EVs, lithium-ion batteries, handicrafts, life-saving medicines.

#### 9. Key Budget Allocations (₹ Crore)

- Defence: ₹4,91,732 | Education: ₹2,66,817 | Health: ₹98,311
- Agriculture: ₹1,71,437 | Infrastructure: ₹1.5 lakh crore

#### 10. Budget Takeaway

- Pro-Growth, Pro-Business Budget with focus on tax relief, infra, AI & MSMEs.
- Fiscal discipline maintained while driving social and economic reforms.
- Challenges: Global risks, inflation, execution of infrastructure projects.

### बजट में एमएसएमई में दिया गया ध्यान

वैस्टर्न यू पी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा चैम्बर सभागार में आज दिनांक 6 फरवरी को केन्द्रिय बजट-2025 पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें चैम्बर के अध्यक्ष डा० रामकुमार गुप्ता जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की सारी मांगे एक ही बजट में पूरी नहीं की जा सकती किन्तु प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस वर्ष के बजट में एमएसएमई, कृषि एवं आमजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि आयकर में जो छूट मिली है उससे जो धनराशि बचेगी उसका कुछ हिस्सा निवेश होगा अथवा कुछ खर्च किया जायेगा जिससे बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ेगी और लोगों के माध्यम से वह धनराशि बाजारों में पहुँचेगी, जोकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। सीए नितिन मलिक, सीए के पी सिंह, सीए पीयूश अग्रवाल, सीए प्रणव गुप्ता एवं सीए जितेन्द्र मोहन ने भाग लिया और बताया कि बजट के सभी प्राविजन 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

अपडेटेड इंकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा को 24 माह से बढ़ाकर 48 माह करने का प्रस्ताव किया गया है। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए टैक्स व्यवस्था में सुधार किया गया है 12 लाख तक की आय को करमुक्त करने से लोगों के पास खर्च करने का पैसा ज्यादा होगा जिससे मार्केट में चल रही मंदी दूर होगी। यदि कोई व्यापारी गलती से सीमा शुल्क अधिक दे देता है तो जटिल प्रक्रिया के कारण शुल्क वापिस लेने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता था किन्तु अब व्यापारी स्वैच्छिक दावा करके एक माह के अंदर शुल्क वापिस ले सकेगा। कच्चे माल का आयात करके उससे भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने पर शुल्क में छूट का प्राविधान है किन्तु इस छूट का लाभ लेने में अभी तक बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था लेकिन 2025 के बजट में इन नियमों में भी संशोधन किया गया है।

चैम्बर सदस्य एव कार्यक्रम के कोडिनेटर श्री आषुतोश अग्रवाल जी ने कहा कि भारत सरकार ने आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण इंजन के रूप में एमएसएमई के विकास पर फाइनेंस बिल 2028 के माध्यम से जोर दिया है। नवीनतम नीति संशोधन और प्रोत्साहन का उद्देश्य एमएसएमई को मजबूत करना और मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

एमएसएमई वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन और बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी का केन्द्रिय बजट 2025 में प्रमुख प्रभाव है। बजट मुख्य रूप से युवाओं और उद्योगों पर केन्द्रित है।

एमएसएमई व निर्यात के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। बैठक में एमएसएमई क्षेत्र पर बजट से पड़ने वाले अनुकूल प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में अध्यक्ष डा रामकुमार गुप्ता, श्री एस पी देषवाल, श्री आषुतोश अग्रवाल, श्री गौरव जैन, श्री राजकुमार कंसल आदि उद्यमी सदस्यों ने भाग लिया।

## RBI tightens norms for imposing penalty under payment systems law

The Reserve Bank tightened norms for imposing monetary penalties and compounding offences under the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) to rationalise and consolidate enforcement action by the central bank.



As per the revised framework for payment system operators and Banks, operation of a payment system without authorisation, disclosure of information, which is prohibited, and failure to pay the penalty imposed by the Reserve Bank within the stipulated period are among the contraventions under the PSS Act.

"(The) Reserve Bank is empowered to impose a penalty not exceeding Rs 10 lakh or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more, in case of contraventions/defaults...", said the 'Framework for imposing monetary penalty and compounding of offences under the Payment and Settlement Systems Act, 2007'.

Earlier, the RBI was empowered to impose a penalty not exceeding Rs 5 lakh. The amount was raised following the enactment of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, which came into force on January 22, 2024.

In cases where such contravention or default is a continuing one, a further penalty of up to Rs 25,000 for every day after the first, during which the contravention or default continues, can also be imposed.

The PSS Act, it said, empowers an officer of the Reserve Bank duly authorised by it on this behalf to compound contraventions, not being an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and fine. The RBI further said only material contraventions will be taken up for enforcement action in the form of

imposition of monetary penalty or compounding of offences.

The framework also provides procedures for imposing monetary penalties and determining the amount of penalty.

## **Bank credit to MSMEs growing faster than credit to large enterprises: Economic Survey - 2025**

Bank credit to MSMEs has been growing faster than credit disbursement to large enterprises, according to the Economic Survey tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday. As of the end of November 2024, credit to MSMEs registered a year-on-year growth of 13 per cent, whereas it stood at 6.1 per cent for large enterprises.

To facilitate credit to MSMEs, a revamp of the Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was undertaken with Rs 9,000 crore in the corpus of the Credit Guarantee Fund Trust for MSEs. This aimed to facilitate an additional Rs 2 lakh crore credit for MSEs at reduced interest rates.

Consequent to this, the survey said the credit limit for guarantee coverage under the scheme was enhanced from Rs 2 crore to Rs 5 crore, and the annual guarantee fees across all segments were reduced by 50 per cent.

In FY23, 11.65 lakh guarantees amounting to Rs 1 lakh crore were given. The government also made special provisions for informal micro

As per the revised framework for payment system operators and Banks, operation of a payment system without authorisation, disclosure of information, which is prohibited, and failure to pay the penalty imposed by the Reserve Bank within the stipulated period are among the contraventions under the PSS Act.

"(The) Reserve Bank is empowered to impose a penalty not exceeding Rs 10 lakh or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more, in case of contraventions/defaults..." said the 'Framework for imposing monetary penalty and compounding of offences under the Payment and Settlement Systems Act, 2007'.

Earlier, the RBI was empowered to impose a penalty not exceeding Rs 5 lakh. The amount was raised following the enactment of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, which came into force on January 22, 2024.

In cases where such contravention or default is a continuing one, a further penalty of up to Rs 25,000 for every day after the first, during which the contravention or default continues, can also be imposed.

The PSS Act, it said, empowers an officer of the Reserve Bank duly authorised by it on this behalf to compound contraventions, not being an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and fine. The RBI further said only material contraventions will be taken up for enforcement action in the form of

enterprises (IMEs) under the existing credit guarantee to avail credit easily. Highlighting the issue of delayed payments faced by MSEs, the survey said from the date of launch of the delayed payment monitoring portal MSME SAMADHAAN, over 2.20 lakh have been filed by MSEs, out of which 20,652 have been mutually settled, 53,493 are yet to be viewed by MSE facilitation councils, 60,714 have been rejected, 45,952 cases have been disposed and 39,893 cases are under consideration.

To boost credit to MSMEs, the government on January 29 approved the Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs (MCGS- MSME) for providing 60 per cent guarantee coverage by National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) to banks and other lenders for up to Rs 100 crore loan sanctioned to eligible MSMEs under MCGS-MSME for purchase of equipment or machinery.

The scheme will be applicable to all loans sanctioned under MCGS-MSME during the period of four years from the date of issue of operational guidelines of the scheme or till cumulative guarantee of Rs 7 lakh crore are issued, whichever is earlier.

## **DGFT upgrades platform for issuing electronic certificate of origin**

The commerce ministry said this upgraded platform offers features such as multi-user access, which enables exporters to authorise multiple users under a single Importer Exporter Code (IEC)



The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), under the commerce ministry, has launched an upgraded system for issuance of electronically generated certificate of origin to help exporters.

Certificate of origin is a key document required for exports to those countries with which India has trade agreements. An exporter has to submit the certificate at the landing port of the importing country.

The document is important to claim duty concessions under free trade agreements. This certificate is essential to prove where the goods come from.

The commerce ministry said this upgraded platform offers features such as multi-user access, which enables exporters to authorise multiple users under a single Importer Exporter Code (IEC).

Additionally, the system now supports Aadhaar-based e-signing alongside digital signature tokens

"The DGFT has launched the enhanced Certificate of Origin (eCoO) 2.0 system, a significant upgrade designed to simplify the certification process for exporters and enhance trade efficiency," it said.

From January 2025, the electronic filing of non-preferential certificates of origin has become mandatory through this platform.

"This trade facilitation initiative has been streamlining the certification process, and improving turnaround times for exporters," the ministry said, adding that the platform processes over 7,000 certificates per day.

These certificates cater to goods not of Indian origin, intended for re-export, trans-shipment, or merchanting trade. "Issued based on documentary evidence from the foreign country of origin, the Back-to-Back CoO ensures transparency and accuracy by explicitly mentioning details of the origin and supporting documents".

## **UP govt approves new aerospace and defence policy, reforms in FDI**

The Uttar Pradesh government approved a new Aerospace and Defence Unit policy to attract Rs 50,000 crore of investments and generate jobs for 1 lakh people.

The state cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath in Prayagraj also approved an FDI policy among 10 key proposals aimed at accelerating the state's development. Among these, the groundbreaking Aerospace and Defence Unit and Employment Promotion Policy 2024 was introduced to position UP as a leader in the sector, the release said. The policy sets an ambitious target of attracting Rs 50,000 crore in investments, with the potential to generate direct employment for 1 lakh youth across the state.

The state Cabinet also approved the new FDI Policy to boost setting up of foreign industries in Uttar Pradesh in order to propel industrial and economic growth.

"Under this policy, the state government will offer up to 80 per cent subsidy on land to the foreign firms

investing in the state. Additionally, major reforms have been introduced in the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy to further boost industrial development," it said.

fostering innovation, and promoting global collaboration to enhance national security and economic prosperity," it added.

The policy aims to strengthen the aerospace and defence (A&D) sector in Uttar Pradesh by creating a robust, hi-tech, and efficient A&D manufacturing ecosystem within the UP Defence Industrial Corridor (UPDIC).

It also seeks to attract startups and investments for the development of state-of-the-art facilities in the sector, the government said.

A&D-based common facility centers are planned to enhance the skills and capacities of startups and MSMEs in the UPDIC. The policy further aims to attract large A&D manufacturing projects and DPSUs, while promoting research and innovation, ensuring UP becomes a pivotal contributor to India's defence and aerospace landscape, it added.

Chief Minister Adityanath said the policy aims to drive the growth of companies that align with India's vision of self-reliance in the Aerospace and Defence (A&D) sector. "The new policy encourages establishment of artificial intelligence and software development centres in A&D. It targets an investment of Rs 50,000 crore over the next five years and promises employment opportunities for 1 lakh youth," the statement said.

The policy offers significant incentives, including front-end subsidies for A&D units, land subsidies, stamp duty exemptions, and capital subsidies. Additionally, the Yogi government will provide benefits like exemptions on transportation charges, with special provisions for women entrepreneurs to encourage their participation in the sector.

The UP government said that the Ministry of Defence has set an ambitious target to double the country's A&D production to USD 25 billion and exports to USD 5 billion by 2025-26. By 2047, the A&D manufacturing sector is expected to contribute 25 per cent to the nation's GDP.

"To achieve these goals, two defence industrial corridors have been established in India in Uttar Pradesh and Tamil Nadu positioning UP as a key player in this transformative vision," it noted.

The Cabinet also approved the subsidy payment to UPSIDA (UP State Industrial Development Authority) for the land allotted to M/s Ashok Leyland Ltd. under the front-ended land subsidy provision of the Incentive Policy 2023, aimed at encouraging FDI and investments from Fortune 500 companies.

"The Empowered Committee's recommendation from September 27 regarding this subsidy payment has been accepted," it noted in the statement. As per the FDI Policy 2023, 75 per cent of the land cost, amounting to Rs 106.51 crore, is payable to UPSIDA for the land provided to Ashok Leyland.

The proposed project will initially establish a facility with a production capacity of 2,500 buses per year, along with a centre of excellence. The total project cost is estimated at Rs 186 crore, it said.

The Cabinet has approved the recommendations of the High-Level Authorized Committee (HLEC), chaired by the Chief Secretary, during its meetings in August and September 2024. Under the Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022, special facilities and concessions have been sanctioned for mega-category industrial units in the state, it said.

"As part of this initiative, Rs 250 crore has been approved as a capital subsidy for Triveni Engineering and Industries Ltd in Moradabad, and Rs 10,749 crore as SGST reimbursement for Gallant Ispat Ltd. in Mirzapur," it added. UP cabinet approves establishment of independent Prosecution Directorate

The Uttar Pradesh government on Wednesday approved the establishment of an independent prosecution directorate.

The decision was announced in a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath in Prayagraj.

The move aligns with the implementation of the Indian Civil Defence Code 2023, aimed at ensuring impartial prosecution in the state, an official statement said.

"The Prosecution Directorate will function independently, with a Director of Prosecution and Deputy Directors appointed as per the state government's directives," it said.

"The existing staff of the Prosecution department will be integrated into the new directorate under Section 20 of the Indian Civil Defence Code 2023. Additionally, separate funding will be allocated for the directorate's future operations, ensuring its effective functioning," it added.

As part of the new proposal, each district will have its own Prosecution Directorate, which will be led by a Director of Prosecution, who will work under the administrative control of the Home Department, the statement said.

"To qualify for the role of Director, a candidate must have at least 15 years of experience as an advocate or prosecutor or must have served as a session judge," it added.

The state government will have the authority to remove the director from their position before completion of their three-year tenure if they are found involved in criminal, or corruption cases, or deemed unable to perform their duties effectively, it said.

The selection and appointment of the director will be carried out by a search committee led by the Additional Chief Secretary or Principal Secretary of the Home Department, it added.

Other members of the committee will include the Principal Secretary of Justice and Legal Counsel, the Director General of Police, and the Secretary of the Home Department. The committee will decide the selection process independently, according to the statement. "The minimum tenure for the Director of Prosecution will be three years. The state government will create permanent and temporary positions

for the directorate's headquarters, regional offices, and district offices to ensure its smooth operation," it noted.

The statement mentioned that at the district level, the District Magistrate will play a key role in overseeing and reviewing the prosecution activities and the work of the prosecution office.

## **RBI forms new advisory committee to evaluate licenses for Universal and Small Finance Banks**

**The RBI has announced the setting up of a Standing External Advisory Committee (SEAC), which will evaluate applications for Universal Banks as well as Small Finance Banks (SFBs).**

The Reserve Bank of India (RBI) has announced the setting up of a Standing External Advisory Committee (SEAC), which will evaluate applications for Universal Banks as well as Small Finance Banks (SFBs). The tenure of the SEAC will be for three years. In a release, RBI said that the secretarial support to the committee would be provided by the Department of Regulation, Reserve Bank of India. The committee, it said, will be headed by MK Jain, former Deputy Governor, Reserve Bank of India, as the chairperson and will have five members. These five members included Re-vathy Iyer, Director, Central Board, Reserve Bank of India, Parvathy V Sundaram, former Executive Director, Reserve Bank of India, Hemant G

Contractor, former MD, State Bank of India and former Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), and Shri NS Kannan, former MD & CEO, ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd.

According to the licensing guidelines, applications for Universal Banks and Small Finance Banks will be initially screened by the Reserve Bank to ensure prima facie eligibility of the applicants. It was also stated that a Standing External Advisory Committee (SEAC) comprising eminent persons with experience in banking, financial sector and other relevant areas, will evaluate the applications thereafter. Before this, the RBI had announced the composition of the previous SEAC vide press release dated March 22, 2021.

## **India to work with EU on developing modern tech, says Piyush Goyal**

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India would work with the European Union to develop cutting-edge technologies and secure critical raw material supply chains to strengthen economic ties. These issues were discussed during a meeting between Goyal and Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security on January 18-19 in Brussels.

The two leaders also agreed to build a commercially meaningful trade agenda and work towards a mutually beneficial Free Trade Agreement (FTA).

The commerce and industry ministry in a statement on Sunday said that India would build a commercially meaningful trade agenda with the EU, which is fair and equitable, addressing the tariff and non-tariff barriers through simplification and cost competitiveness for benefits of businesses from both sides.

"India would work together with the EU for developing cutting edge technologies, secure critical raw material supply chains and build resilient supply chains- reducing dependencies on non-market economies and developing closer economic ties between India and the EU," it said. Both sides also discussed increasing cooperation in the area of trade and sustainable development in a fair manner keeping in mind the respective level of developments and the principle of common but differentiated responsibility.

"The two leaders outlined political directions to both the teams to develop a mutually beneficial agenda for trade and investment and a robust FTA in an expedited manner to meet global challenges," the ministry said. They reviewed progress in the trade and investment group of the India-EU Trade and Technology Council (TTC), agreed to address legacy issues and laid a roadmap for continuous consultations between senior officials from both sides and at ministerial level.

## **RBI Introduces Measures To Boost Cross-Border Transactions In Indian Rupee**

To encourage greater use of Indian Rupee (INR) for trade transactions, in July 2022, an additional arrangement in the form of Special Rupee Vostro Account (SRVA) was introduced.

The Reserve Bank of India (RBI) announced liberalised norms to encourage use of Indian Rupee and local/national currencies to settle cross border transactions. The decision comes at a time when the domestic currency is sliding and touched an all-time low of US dollar

The Reserve Bank has already signed Memorandum of Understanding (MoU) with the central banks of the United Arab Emirates, Indonesia and Maldives to encourage cross-border transactions in local currencies, including Indian Rupee.

To encourage greater use of Indian Rupee (INR) for trade transactions, in July 2022, an additional arrangement in the form of Special Rupee Vostro Account (SRVA) was introduced. Several foreign banks have since opened SRVAs with banks in India.

"Overseas branches of Authorized Dealer banks will be able to open INR accounts for a person resident outside India for settlement of all permissible current account and capital account transactions with a person resident in India," the RBI said while announcing the changes made in the extant FEMA regulations.

Under the liberalised FEMA regulations, persons resident outside India will be able to settle bona fide transactions with other non-residents using the balances in their repatriable INR accounts such as Special Non-resident Rupee account and SRVA. Also, persons resident outside India will be able to use their balances held in repatriable INR accounts for foreign investment, including FDI, in non-debt instruments.

RBI further said Indian exporters will be able to open accounts in any foreign currency overseas for settlement of trade transactions, including receiving export proceeds and using these proceeds to pay for imports. The decision on promotions of cross border transactions in INR and local / national currencies follows a review of the FEMA regulations of 1999 undertaken by the Reserve Bank in consultation with the central government.

## **DPIIT, ITC join hands to help startups in manufacturing sector**

DPIIT joint secretary Sanjiv said, "We look forward to fostering scalable solutions and transformative growth to ensure a conducive environment of startups.

The department for promotion of industry and internal trade (DPIIT) has entered into a partnership with cigarette-to-consumer goods conglomerate ITC to help startups in the manufacturing sector, according to a statement.

According to the memorandum of understanding (MoU) signed for the purpose, ITC's experience and expertise with the market network will complement DPIIT's initiative for supporting startups across the country.

Under the partnership, ITC will deploy startup solutions in key areas such as digital platforms for manufacturing execution systems, integrating renewable energy opportunities for manufacturing locations, and energy storage systems.

Startup India director Sumeet Kumar Jarangal said this would help provide hassle-free market access to startups, providing unbound opportunities to work out viable solutions as per their organisation's business requirements. "It will focus on digital for increased future-ready and operational excellence in manufacturing, and in the area of renewable energy to expand ITCs sustainable," said Anil Rajput, president of corporate affairs at ITC.

## **Labour ministry to set up career counseling centers in major universities**

In an effort to guide youth towards meaningful career choices and improve employment opportunities, the labour ministry plans to establish career counselling centres in all major universities across India, Union Labour Minister Mansukh Mandaviya announced

“This initiative will be a tripartite effort involving industry bodies like the Confederation of Indian Industry (CII), universities, and the government (labour ministry). It will help students map their career paths more effectively. Skills naturally evolve as demand increases, and students will find this initiative highly beneficial,” the minister said.

The announcement was made at an event jointly organised by CII and the labour ministry, focusing on the future of work and its implications for India’s employment landscape.

By integrating databases such as the National Career Services (NCS) portal, the migrant workers portal, and E-Shram, the proposed career counselling centres aim to create a precise demand-supply map of skills and job opportunities in the market.

The minister also suggested granting industry the status of an establishment to impart skills training tailored to sectoral needs, creating demand-driven, skilled manpower.

Additionally, Mandaviya called for redefining the concept of “jobs” to include self-employment and women engaged in household work to enhance female labour force participation.

“India has manpower, brainpower, and skill power. There is a need to redefine ‘jobs’ to include self-employed individuals and women performing household chores as part of the nation’s workforce,” Mandaviya said.

## **Govt approves 2 new payment methods for rooftop solar under PM Surya Ghar**

The Ministry of New & Renewable Energy has come out with new guidelines, allowing two more payment methods for the installation of rooftop solar system under PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.

The move will ensure payment security as well as the grant of subsidy to households in case of payments through Renewable Energy Service Company (RESCO) and utility-led aggregation models.

The ministry has notified scheme guidelines for implementation of 'Payment Security Mechanism' component and 'Central Financial Assistance' component for RESCO models/ utility-led aggregation models under PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, an official statement said.

Under this scheme, Rs 100 crore has been earmarked for payment security mechanism (PSM) for de-risking investments in RESCO-based grid-connected rooftop solar models in residential sectors, which may be supplemented through other grants, funds and sources after due approval, the statement said.

Under the RESCO model, third-party entities invest in rooftop solar installations, enabling consumers to pay only for the electricity consumed without bearing the upfront costs.